(ख) क्या इन सेवाओं में चयन के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों/अधिमान के बीच कोई नियत अनुपात है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या ये उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के अनुरूप है कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा हेतु कुल अंकों के मध्य अनुपात 1:7 होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और कतिपय संबद्ध सेवाओं में भर्ती, भारत के राजपत्र में अधिसूचित नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा अयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा-परीक्षा के माध्यम से की जाती है।

(ख) सिविल सेवा-परीक्षा की वर्तमान योजना, कोठारी-समिति (1974-76) की सिफारिशों पर विचार करके 1979 में शुरू की गई थी। सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा की योजना में साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 250 निर्धारित किए गए थे तथा उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 1800 निर्धारित किए गए थे। प्रो० सतीश चन्द्र समिति द्वारा परीक्षा की उक्त योजना के संबंध में की गई समीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक बढ़ाकर 300 निर्धारित किए गए और उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 2000 निर्धारित किए गए।

(ग) जी, हां,। साक्षात्कार के अंकों (300 अंक) तथा अधिकतम अंकों (2300 अंक) का अनुपात 13.4 प्रतिशत अर्थात् 1:7.67 है, जो निर्दिष्ट अनुपात की तुलना में ठीक बैठता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

Security for the Investigating Authorities

*89. SHRI RAM GOPAL YADAV:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering to provide full security to the authorities investigating different scandals in the country, keeping in view the sensitive nature of their job and the risk involved to them and the members of their families; and

(b) if so, what decision Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) Whenever such requests for security from the concerned authorities are received, the States and Union Territories are informed about the apprehensions regarding security of the concerned personnel and are requested to provide necessary security to them.

पंजाब और उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*90. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक रोजगार के अवसरों में वृद्धि और गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब और उत्तर प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) और (ख) राज्यों को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती बल्कि उनके स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए ब्लॉक अनुदान के रूप में दी जाती है। तब राज्य विभिन्न क्षेत्रकीय शीर्षों के अंतर्गत अपनी योजना निधियों का आवंटन करते हैं। साथ ही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) भी मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बीएमएस) और गंदी बस्तियों के विकास के लिए भी राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है। विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है। वर्ष 1996-97 के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश की मुहैया कराई गई कुल केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:—

906/RS-2

(करोड़ रुपये में)

		पंजाब	उत्तर प्रदेश
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता (गाडगिल फार्मूला पर आधारित)	212.92	1492.80
2.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
	(क) बुनियादी न्यूनतम सेवाएं (बीएमएस)	25.59	317.33
	(ख) गंदी बस्तियों का विकास	7.05	31.28
3.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	228.71	900.00
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता		
	(क) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	—	229.45
	(ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8.17	—
	(ग) जनजाति उपयोजना	—	1.4

केन्द्र सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए भी राज्यों को निधियां मुहैया कराती हैं। 1996-97 में इन प्रमुख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रमों के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों को मुहैया कराया गया केन्द्रीय आवंटन नीचे तालिका में दिया गया है:—

(करोड़ रुपये में)

कार्यक्रम	पंजाब	उत्तर प्रदेश
ग्रामीण गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रम		
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.61	101.58
जवाहर रोजगार योजना	8.72	338.68
रोजगार आश्वासन स्कीम	—	113.20*
इंदिरा आवास योजना	5.56	216.16
मिलियन वैल्स स्कीम	2.18	84.65
शहरी गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रम		
नेहरू रोजगार योजना	1.15	12.28
प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	2.71	14.45
गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं	0.16	2.82

*दिसम्बर, 1996 तक रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि